पीपुल्स समाचार, भोपाल
25 OCT 2010

प्रदेश में आएगा खुशहाली का दौर

इस इन्वेस्टर समिट से उम्मीद जागी है कि मध्य प्रदेश भी अब आर्थिक संपन्नता की राह पर आगे बढ़ेगा।

खजुराहो में बीते दो दिनों में साइन हुए एमओयू ने उम्मीद जगाई है कि अब हमारे प्रदेश में भी उद्योग-धंधे बढ़ेंगे, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और प्रदेश बढ़ेगा आर्थिक संपन्नता की राह पर। खजुराहो में हुई इन्वेटर्स मीट में समिट में जिस तरह से दो दिनों में कुल 2.35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं उसे देखकर यह लगता है कि उद्योगपतियों को अब देश का हृदय प्रदेश रास आने लगा है। सबसे ज्यादा उम्मीद की किरण जगाई अनिल अंबानी ने, जिन्होंने अगले पांच सालों में 75 हजार करोड़ रुपए का निवेश करने का आश्वासन दिया है। उनके समूह की प्राथमिकता पॉवर, सीमेंट और एज्युकेशन सेक्टर में है। वे प्रदेश में हर साल अब 15 हजार करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा राशि के एमओयू ऊर्जा के क्षेत्र में ही हुए हैं। इस सेक्टर में 1 लाख 33 हजार करोड़ का निवेश प्रदेश में होगा। वैसे क्षेत्रवार देखा जाए तो सबसे ज्यादा 75 हजार करोड़ राशि का निवेश भोपाल, इंदौर और उज्जैन में होगा और सबसे कम ग्वालियर-चंबल संभाग में, महज 155 करोड़। ऐसा शायद वहां पड़ने वाली डकैतियों और फिरौती आदि कि वारदातों के कारण हो। विंध्य प्रदेश में 74 हजार करोड़, महाकौशल में 32 हजार करोड़ और बुंदेलखंड में लगभग 20 हजार करोड़ रुपए का निवेश होगा।

खैर यह तो एक चरण था, लेकिन प्रदेश में निवेश के लिए उद्योगपतियों का रुझान बना रहे इसके लिए अब सरकार को माहौल को बनाए रखने के साथ ही आधारभूत संरचना पर भी ध्यान देना होगा। अनिल अंबानी ने भी कहा है कि सीमेंट और अन्य बड़े उद्योगों के लिए लॉजिस्टिक हब और ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं सरकार को मुहैया करानी होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बात को जानते हैं तभी उन्होंने केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री से आग्रह किया है कि वे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री से प्रदेश से गुजरने वाले सभी नेशनल हाईवे के मरम्मत का आग्रह करें। लेकिन केंद्र से आग्रह के साथ ही श्री चौहान को खुद भी राज्य स्तर पर कुछ प्रयास करने होंगे, जैसा कि केंद्रीय मंत्री श्री यादव ने सलाह भी दी है कि प्रदेश में निवेश को बढ़ाने को टैक्स स्ट्रक्चर में राज्य सरकार सुधार करे। अगर हम समुचित माहौल नहीं देंगे तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे यहां लगने वाले उद्योग दूसरे राज्य में नहीं शिफ्ट हो जाएं, जैसा कि पहले भी हुआ है।